नव भारत
| संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी |

राज्यपालों की भूमिका व संवैधानिक मर्यादा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ताजा फैसला लोकतंत्र की मर्यादा और शासन व्यवस्था की साख को मजबूत करने वाला है. लंबे समय से कई राज्यों में निर्वाचित सरकारों और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बनी रही, जहां राज्यपालों द्वारा विधेयकों को महीनों तक लंबित रखा गया. अदालत ने इस प्रवृत्ति पर सख्त नाराज़गी जताते हुए साफ कर दिया है कि राज्यपाल के पास विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोककर रखने का कोई अधिकार नहीं है. अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए शीर्ष अदालत ने तीन विकल्पों को ही संवैधानिक माना है, विधेयक को मंजूरी देना, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना. अदालत ने कहा कि इन तीन रास्तों के अलावा किसी विधेयक को 'ठंडे बस्ते' में डालकर निष्क्रियता दिखाना संविधान की भावना के विरुद्ध है. यह स्पष्ट रेखांकन उन राज्यों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जहां राजनीतिक मतभेदों के कारण राजभवन विधाई प्रक्रिया के बीच बाधा बनता गया. इस फैसले का पहला बड़ा संदेश है, जवाबदेही. राज्यपाल कोई राजनीतिक पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि एक संवैधानिक प्रहरी हैं. जनता द्वारा चुनी गई सरकार के कामकाज को अटकाना न तो नैतिक है और न ही संवैधानिक. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर निर्णायक रोक लगा दी है, जो लोकतंत्र की बड़ी जीत है.

दूसरा, अदालत ने सहयोगी संघवाद की अनिवार्यता पर जोर दिया है. राज्यों की विधानसभाएं जनता की अदालत से सीधे जुड़ी होती हैं. यदि राज्यपाल ही विधायी प्रक्रिया को रोकते रहें, तो पूरा तंत्र अविश्वास और खींचतान का अखाड़ा बन जाता है. न्यायालय का यह फैसला राजभवन को यह याद दिलाता है कि वह केंद्र की नीति का विस्तार भर नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक संस्था है, जिसका कर्तव्य निर्वाचित सरकार के साथ समन्वय बनाकर चलना है. तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भले कोई सख्त समय सीमा न तय की हो, लेकिन यह जरूर कहा है कि यदि राज्यपाल को किसी विधेयक पर आपत्ति है, तो उसे 'जितनी जल्दी हो सके' वापस भेजा जाए. यह टिप्पणी उन अनावश्यक देरी और प्रशासनिक उदासीनता पर सीधा प्रहार है, जिनके कारण कई बार शासन व्यवस्था ठप पड़ जाती है. यह फैसला राज्यपालों के लिए एक स्पष्ट नसीहत भी है. यह याद रखने की जरूरत है कि राजभवन राजनीतिक रणनीतियों का विस्तार नहीं है. राज्यपालों से अपेक्षा है कि वे राजनीतिक तटस्थता का पालन करें, जनता के जनादेश का सम्मान करें और संविधान की मर्यादा में रहते हुए कार्य करें. 'स्पीड पोस्ट' की तरह समयबद्ध प्रक्रिया अपनाना ही राजभवन की मर्यादा और जनता के विश्वास दोनों की रक्षा करेगा.

राजभवन और सचिवालय के बीच संवाद की कमी से पैदा होने वाले टकराव अब समाप्त होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारतीय संविधान किसी पदाधिकारी को असीमित अधिकार नहीं देता. अब राज्यपालों पर जिम्मेदारी है कि वे इस फैसले की आत्मा को समझें और संवैधानिक गरिमा का पालन सुनिश्चित करें. निश्चित ही, यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करेगा और केंद्र-राज्य संबंधों में जरूरी सामंजस्य की राह खोलेगा. यह न केवल संवैधानिक मर्यादाओं को पुनर्स्थापित करता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है और उसे रोकने की कोई गुंजाइश अब शेष नहीं है.

मध्य क्षेत्र की डायरी

मध्यप्रदेश में नशे से मौत के सौदागरों पर कसें शिकंजा

दिलीप झा

प्रदेश को नशामुक्त बनाने की बातें वर्षों से हो रही है लेकिन विडंबना है कि इसमें सफलता नहीं मिल रही है. हर दूसरे तीसरे दिन राजधानी समेत प्रदेश के महानगरों में नशे की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है. पुलिस तो पकड़ने का अपना काम कर रही है, लेकिन युवाओं को नशे की दल दल में धकेलने के पीछे कौन कौन सफेदपोश लोग हैं, उन्हें बेनकाब किया जाना बेहद जरूरी है. क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी अगर नशे की लत से जकड़ जाएगी तो उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है.

सूत्र बताते हैं कि भोपाल, जबलपुर और इंदौर नशे के सौदागरों का बड़ा अड्डा बन गया है. इन महानगरों में राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब से यहां गांजा, चरस , अफीम एवं एमडी ड्रग्स की सप्लाई होती है और फिर छोटे शहरों के युवाओं को नशे के दल दल में धकेल दिया जाता है. सरकार को यह भलीभांति समझना चाहिए कि युवा जब नशे में लिप्त होते हैं तो यही से आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं. गत दिनों भोपाल से एमडी ड्रग्स के साथ एक महिला को पुलिस ने पकड़ा है और बुधवार 19 नवंबर को हरदा जिले से पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने 490 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है,जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 98 लाख रुपए बताई जा रही है. लोग सरकार से सबसे अहम सवाल यह कर रहे हैं कि आखिर एमडी ड्रग्स की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब लगेगा क्योंकि समाज पर इसका बहुत बुरा असर पर रहा है. नशे की चपेट में आने से घर परिवार बिखर रहा है. ? पिछले साल भी राजधानी भोपाल से भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स पकड़े गए थे. लेकिन उस मामले में भी बहुत बड़ा खुलासा नहीं किया गया.

मोहन सरकार को क्या करना चाहिए

मध्य प्रदेश मे पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड से काम करने की छूट देनी चाहिए. पुलिस पर राजनीति जब हावी होने लगती है पुलिस की प्रशासनिक गाड़ी डिरेल हो जाती है. इसके पीछे का लॉजिक भी हमें समझना होगा कि जब राजनैतिक हलकों से किसी अपराधी को छुड़ाने के थाना पुलिस पर दवाब बनता है तो पुलिस का मनोबल गिरता है. पुलिस को अपरिहार्य कारणों से जब अपराधियों को छोड़ना पड़े तो जाहिर है उनमें नाराजगी होती है.

अपराधियों को पकड़ने अथवा अपराध के तह में जाने के लिए पुलिस प्रशासन को गहन पड़ताल करनी होती और तमाम कठिनाइयां के पापड़ बेलने पड़ते हैं. ऐसे में जब राजनैतिक गलियारों से थाने में फोन आता है कि उक्त अपराधी को छोड़ दें तो सोचिए कि क्या किसी पुलिस अधिकारी पर क्या गुजरता होगा. यह ध्रुव सत्य है पुलिस के मनोबल को बढ़ाए बिना आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण कतई संभव नहीं है. राजनीतिज्ञों को इस पर गहनता से विचार करना होगा कि पुलिस के कार्यक्षेत्र में वो दखल नहीं दे. कुछ राजनेता अर्थात माननीय अपने वोट बैंक के कारण अपराधियों को बचाने के लिए उनके साथ अप्रत्यक्ष रूप से खड़े हो जाते हैं और इसका बड़ा खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है. सूत्रों का कहना है कि विधायकों का थाने में हस्तक्षेप बढ़ने के कारण टीआई भी अपने मन से पुलिसिंग नहीं कर पाते हैं.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर एमपी पुलिस

दिल्ली ब्लास्ट के तार मध्यप्रदेश से जुड़ने के बाद यहां की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है. अलफलाह यूनिवर्सिटी के संचालक जवाद अहमद सिद्दीकी मूल रूप से इंदौर के महू का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि उसने 25 पहले एक निवेश कंपनी खोलकर हजारों लोगों का करोड़ों रुपये का चूना लगाया है. वह पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए महू से भागकर फरीदाबाद में आतंक की फैक्ट्री खोलकर बैठ गया. इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को यूनिवर्सिटी चलाने की अनुमति किसने और क्यों दी? सबसे हैरानी की बात है कि अभी तक वह पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आया.? किसकी मेहरबानी इस पर थी, किसके शह पर देश विरोधी गतिविधियों में वह लिप्त था जैसे तमाम सवालों के जवाब सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस दोनों को चाहिए. हालांकि इस मामले में नित नए खुलासे उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी हो रहे हैं. एनआईए ने तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है. आतंकियों ने 32 कारों में विस्फोटक लेकर पूरे देश में विस्फोट करने का षड्यंत्र रचा था. लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में बड़ी मुस्तैदी के साथ आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और हजारों लोगों की जान बच गई.

जुगाड़ बार-बार, नीतीश बने सीएम10वीं बार

नीतीश के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का कारण सिर्फ उनकी लोकप्रियता भर नहीं है, इसमें उनके फॉर्मूला मास्टर होने का भी योगदान है. वर्तमान में भारत की चुनावी राजनीति का फॉर्मूला लगता है, अब एक नए संक्रमणकाल से गुजर रहा है. भारतीय लोकतंत्र की चुनावी यात्रा के अब तक के सफर में नए प्रचलन स्थापित हो रहे हैं. पहले पिछड़ी दलित अगड़ी और अल्पसंख्यक मुस्लिम के आधार पर पार्टियां मतदाताओं का समीकरण तैयार करती थीं, अब वह वर्गीकरण दरकना शुरू हो चुका है. अब मुख्य रूप से तीन राजनीतिक वर्ग रेखांकित हो रहे हैं, ये हैं किसान, युवा और महिला. इसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक वर्ग महिला का बना है. किसान और युवा पहले भी राजनीतिक दलों का इमोशनल डोमेन हुआ करता था पर अब महिला मतदाता का जेंडर समूह एक बड़ा पॉलिटिकल डोमेन बनकर उभरा है, क्योंकि संख्या के हिसाब से यह आधी आबादी है. महिलाओं के लिए प्रावधानित मासिक या एकमुश्त भत्ता दिए जाने की जो होड़ लगी है चाहे उन्हें आजीविका के साधन के नाम पर दिया जाए, चाहे युवा महिला वर्ग की पढ़ाई और छात्रवृति के रूप में दिया जाए या फिर लड़की की शादी के लिए दिया जाए.

गौरतलब है कि महिलाओं के लिए धन स्थानांतरण के इस राजनीतिक आइडिया को कई जगह योजना का रूप दिया गया. जैसे मध्य प्रदेश में लाड़ली बहन योजना, कहीं धनलक्ष्मी योजना, तो कहीं महिला आजीविका योजना के रूप में ये दृष्टिगोचर हुआ. इस क्रम में हरियाणा की सैनी सरकार, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले महिलाओं के आर्थिक हितों की इन घोषणाओं को योजनाओं में अंजाम दिया. इसका परिणाम ये हुआ कि इन तीनों प्रदेशों में पदारूढ़ सरकारें पुन: विजयी हो गई. यही प्रयोग बिहार की पदारूढ़ सरकार ने भी प्रदेश की 75 लाख महिलाओं को दस हजार की एकमुश्त आजीवका कमाई की राशि के रूप में स्थानांतरित कर किया है.

हर राज्य में चुनावी रेवड़ी- कुल मिलाकर मुफ्त और रेवड़ी भारतीय लोकतंत्र की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा फॉर्मूला बनकर उभरा है. बताया जाता है कि बिहार सरकार को महिला आजीविका के एवज में कुल 40000 करोड़ की राशि स्थानांतरित करनी पड़ी है. इससे पूर्व रेवड़ी की राजनीति शुरू करने के एवज में कांग्रेस शासित कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई. इसी तरह महाराष्ट्र में भी लाड़की बहीण योजना से खजाने पर भारी बोझ पड़ा है. प्रश्न ये है इस बोझ से कैसे निपटा जाएगा? देश के कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनके घरेलू राजस्व कमाई की हिस्सेदारी उनके कुल बजट में दो तिहाई से ज्यादा है जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं पर बिहार शराबबंदी की वजह से पहले से ही करीब 5 से 10 हजार करोड़ सालाना राजस्व का नुकसान उठा रहा है. उसे मुफ्तखोरी की मार ज्यादा झेलनी पड़ेगी बशर्ते डबल इंजन की सरकार से उसे अतिरिक्त वित्तीय ताकत प्राप्त हो. चुनाव में लोकलुभावनवाद और रेवड़ी संस्कृति पर भी दो वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों की एक लक्ष्मण रेखा तय किए जाने की पुरजोर वकालत की गई. पर प्रतियोगी चुनावी व्यवस्था में कोई भी दल इस पर अभी तक उसी तरह से हामी नहीं भर पाए, यदि बिहार की बात करें तो सत्तारूढ़ दल ने अपनी घोषणा पर 40 हजार करोड़ खर्चे. हालांकि बिहार का चुनावी परिणाम केवल रेवड़ी का खेल था, ऐसा नहीं कहा जा सकता बल्कि नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए का भरोसा भी लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा था, जिस तथ्य को सभी राजनीतिक पंडितों को स्वीकार करना पड़ा.

-मनोहर मनोज

महिलाओं का मिला भारी समर्थन

चुनावी पंडितों की तमाम नकारात्मक भविष्यवाणियों के बावजूद आखिरकार नीतीश कुमार बिहार के 10 वीं बार मुख्यमंत्री बन गए. इसी के साथ ही उन्होंने संख्या के हिसाब से देश में किसी भी राज्य के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी बना दिया, लेकिन ज्यादा समय तक, दिनों के हिसाब से मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग का है. वह 24 साल 165 दिनों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं.

आतंकी मामलों का शीघ्र निपटारा आवश्यक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह एनआईए मामलों को जल्दी निपटाने में सहयोग दे. इसके लिए सरकार को 6 माह की मुद्दत दी गई है. देश में न्याय की गति धीमी है जिसकी एक वजह जजों की कमी मानी जाती है. जुलाई में देश के उच्च न्यायालयों में जजों के 371 पद खाली थे. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखने के लिए 50 स्वीकृत एनआईए अदालतों में से 3 ने केवल एनआईए मामलों पर गौर किया. इसका अर्थ यह है कि इन अदालतों के जज सामान्य आपराधिक मामलों और बड़े आतंकी मामलों के बीच अपना समय बांट लेते हैं. दूसरी ओर हजारों विचाराधीन कैदी जेल में रहने को बाध्य है जिनकी जमानत हो सकती है. इनमें गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग और बुजुर्ग शामिल हैं. आतंकवाद को वित्त पोषण (फंडिंग) के मामले में बारामूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख लंबे समय से जेल में कैद हैं. उन्हें संसद सत्र में भाग लेने के लिए हर बार पैरोल लेना पड़ता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में चेतावनी दी थी कि यदि एनआईए के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में बहुत अधिक विलंब हुआ तो वह विचाराधीन कैदियों को रिहा कर देगा. तब से सरकार एनआईए अदालतों को मजबूत करने की दिशा में प्रयत्नशील है.

गत 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के निकट हुए विस्फोट के बाद रिक्त पदों पर भर्ती को प्राथमिकता देनी होगी ताकि आतंक के गुनहगारों को यथाशीघ्र सजा मिल सके.

देश के 11 राज्यों से इस संबंध में बात चल रही है लेकिन 10-12 विशेष एनआईए अदालतों की स्थापना के लिए जगह की समस्या सामने आ रही है. इतना ही नहीं, एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के पास स्टाफ की भी समस्या है जिसकी वजह से जांच धीमी पड़ जाती है. इसमें 1,901 पद स्वीकृत हैं जिनमें से जून माह में 541 या 28 प्रतिशत पद खाली पड़े थे. इनमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों का समावेश है. गत 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के निकट हुए विस्फोट के बाद इन पदों पर भर्ती को प्राथमिकता देनी होगी ताकि आतंक के गुनहगारों को यथाशीघ्र सजा मिल सके. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस दिशा में 16 दिसंबर तक पक्का निर्णय लेने को कहा है.

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

निशानेबाज

भाजपा के पास जीत का प्लान बंगाल में चलाएगी अभियान

पड़ोसी ने हमसे कहा, 'निशानेबाज, बिहार चुनाव की जीत से बीजेपी बल्ले-बल्ले है. अब उसके निशाने पर बंगाल है. उसके नेताओं को पूरा भरोसा है कि ममता की छांव में पल रहे बंगाल से घास-फूस की तरह तृणमूल कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे. मोदी मैजिक से प्रभावित बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिल से आवाज उठ रही है- मन में है विश्वास पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन!

हमने कहा, 'बिहार में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव निपट गया जबकि बंगाल में 6-7 चरण में इलेक्शन करवाना पड़ता है. वजह यह है कि बंगाल में जमकर चुनावी हिंसा होती है और बम फूटते हैं. चुनाव आयोग के लिए वहां चुनौतियां ही चुनौतियां हैं. वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान हथेली पर रखकर काम करना पड़ता है.'

पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, यह सब पुरानी बातें हो गईं. अब बीजेपी के पास चुनाव जीतने का शानदार फॉर्मूला मौजूद है जिसे वह चाहे तो पेटेंट करा सकती है. उसे मालूम है कि यूपी का 'जय श्रीराम' नारा दुर्गा पूजा वाले बंगाल में

काम नहीं करेगा. ममता के पास मुस्लिम वोटर हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते. इतने पर भी बीजेपी अपनी प्लानिंग में लगी हुई है. जब बंगाल विधानसभा चुनाव आएगा तब प्रधानमंत्री मोदी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जैसी लंबी दाढ़ी बढ़ा लेंगे. बांग्ला भाषा के कुछ वाक्य बोलकर भाषण की शुरूआत करेंगे तथा अपनी सभाओं में ममता बनर्जी को 'दीदी ओ दीदी' कहकर ललकारेंगे.'

हमने कहा, 'यह दांव-पेंच पुराने हो गए. अब मोदी-शाह और उनकी पार्टी को कोई नया फंडा आजमाना होगा.'

पड़ोसी ने कहा, 'बीजेपी के पास हर ताले की चाबी मौजूद है. पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में उसने टीएमसी में बगावत करवाई थी और शुभेंदु अधिकारी व उनके छोटे भाई सौमेंदु अधिकारी को अपने पाले में खींच लिया था. बीजेपी सिर्फ नारियल नहीं, राज्यों की पार्टियां भी फोड़ा करती है. विभीषण या जयचंद किसी भी पार्टी में मिल जाते हैं. एसआईआर से लाखों वोटरों के नाम काटे जाते हैं इसके अलावा चुनाव के ठीक पहले वह महिलाओं के खाते में करोड़ों की रकम जमा करवा देती है. हर लेडी के अकाउंट में सीधे 10,000 डालो और वोट पक्के समझो. चुनाव आयोग के पास उस ओर देखने का चश्मा नहीं है. यह है बीजेपी की जीत का आजमाया हुआ फार्मूला !'

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD 12088 - डॉ. सागर खादीवाला

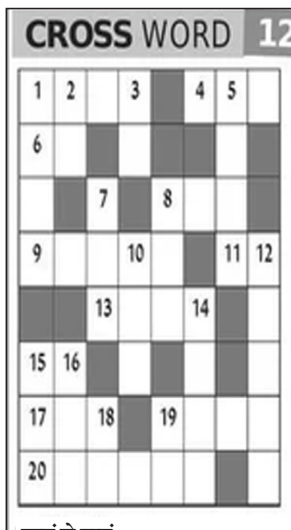

बाएं से दाएं

1.हस्ताक्षर किया हुआ, जिसमें हस्ताक्षर किए हुए हो (सं.) 4. दुर्योधन का मामा (महाभारत) 6. उम्र, अवस्था (सं.) 8. सहज, सुगम, निष्कपट 9. इंद्रवधू, गहरे लाल रंग का एक बरसाती कीड़ा 11. परिमाण, माप 13. खिसकना 15. पर्याप्त, भरपूर, ठहरो 17. लीन या अनुरक्त करना 19. गिनना, अनुसंधान, खाते में जमा करना (सं.) 20. जिसकी आंखें अश्रुपूर्ण हो

ऊपर से नीचे

1. जो अपने भरोसे या सहारे पर रहता हो 2. ह्रास, नाश, यक्ष्मा रोग (सं.) 3 गरम, तपाया हुआ, कृद्ध (सं.) 5. किसी भारी वस्तु से जोर से दबाना, पैरों से रौंदना 7. लाचार, विवश, असहाय (उर्दू) 8. बिल्कुल ठीक, व्याख्या सहित 10. चुभाना, गाड़ना, ठेलना 12. किसी वस्तु की आकृति रंग-गुण दोष आदि से, परिचित होना, किसी पूर्व परिचित व्यक्ति या वस्तु को देखकर यह जान लेना कि वह अमुक है 14. किसी काम में या किसी निर्वाचन में होने के लिए किसी का नाम लिखा जाना 15. वर्ष, साल 16. समूह, समुदाय 18. नली, अर्धचंद्राकार लोहे का टुकड़ा जो जूते या घोड़े की टाप में लगाया जाता है 19. आमदनी

Solution 12087

मे	घ	ना	द	■	उ	त	ना
रू	र	■	स्त	ब्ध	ता	■	म
ला	■	सा	र	■	र	सि	क
■	म	य	खा	ना	■	स	■
आ	न	बा	न	■	प्र	क	ट
जा	मु	न	■	ना	च	ना	■
■	टा	■	घा	य	ल	■	सा
पा	व	रो	टी	■	न	से	नी

ज्योतिषाचार्य प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन लाभ का योग है, वर्ष के मध्य में व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, शासन सत्ता का सुख प्राप्त होगा, वर्ष के अन्त में शारीरिक कष्ट होगा, मित्रों से व्यर्थ विवाद होगा, स्थानान्तरण का योग है, मानसिक तनाव में वृद्धि होगी.

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट होगा, वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को व्यर्थ में मित्रों का विवाद हो सकता है, कर्क राशि के व्यक्तियों का शासन सत्ता का सुख प्राप्त होगा, मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को आकस्मिक धन प्राप्त होगा, धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को मानसिक तनाव रह सकता है, स्थान परिवर्तन का योग है, सिंह राशि के व्यक्तियों को राजकीय सहयोग मिलेगा, मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक हंसमुख, मिलनसार होगा, जन्म स्थान सू दूर रहकर अपनी उन्नति करेगा, अपनी मनमर्जी का मालिक होगा, आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, विशेष विद्या का ज्ञाता होगा.

मेष- लाभकारी योजना बनेगी, भावनात्मक संबंधों में मधुरता आयेगी, विशेष श्रम एवं प्रयास करने का योग है, मन: स्थिति संतोषप्रद रहेगी.

वृषभ- मेहमानों की आवाजाही से घर में उल्लास का माहौल रहेगा, नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, शीघ्र कार्य शुभारंभ होगा, मित्रता उपयोगी रहेगी.

मिथुन- समय पर कार्य न होने से परेशानी होगी, नौकरी संबंधी प्रयासों में सफलता मिलेगी, राजकीय सहयोग मिलेगा, सुविधाओं की वृद्धि होगी.

कर्क- विरोधी की चालों से सावधान रहें, राजकीय मामले आपसी बातचीत से सुलझ सकते हैं, धार्मिक सत्संग से मानसिक शांति रहेगी, नियमितता से कार्य करें.

सिंह- आय के नये स्त्रोत बनेंगे, शारीरिक शिथिलता रहेगी, पूज्य व्यक्ति की सलाह उपयोगी सिद्ध होगी, विवादों को टालने का प्रयास करें.

कन्या- सहूलियत के हिसाब से कार्य योजना में परिवर्तन कर लेंगे, अधिकारी सहमत होंगे, व्यवसायिक कार्यों की अधिकता रहेगी.

तुला- अनुभवी लोगों की सलाह से दुविधा दूर होगी, खानपान पर ध्यान रखें, आर्थिक लेनदेन में सावधानी, कार्य की अधिकता रहेगी.

वृश्चिक- अनहोनी का भय रहेगा, सामाजिक कार्य में आपकी उपस्थिति प्रसन्नता देगी, संतान के कारण भावनात्मक पीड़ा हो सकती है, खानपान पर संयम रखें.

धनु- कार्यस्थल पर सुधार के लिये दिन-रात एक कर देंगे, दाम्पत्य सुख मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मित्रों का समागम होगा.

मकर- जरूरी कार्य के लिये किसी का सहयोग लेना पड़ेगा, मित्र के रूखे व्यवहार से खिन्नताहोगी, शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ेगा, लाभ में कमी आयेगी.

कुम्भ- कार्य की गति धीमी होने से परेशानी होगी, लेनदेन की चिन्ता रहेगी, आकस्मिक खर्च होने का योग है, निजी पुरूषार्थ बना रहेगा.

मीन- स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पायेंगे, समय पर सोचे हुये कामकाज बनने का योग है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, विद्यार्थी वर्ग को परिश्रम होगा.

उदयकालीन ग्रह चाल

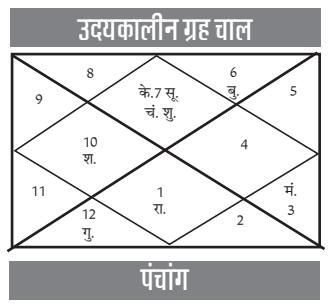

पंचांग

रा.मि. 01 संवत् 2082 मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया शनिवासरे दिन 3/12, ज्येष्ठा नक्षत्रे दिन 3/52, सुकर्मा योगे दिन 11/33, कौलव करणे सू.उ. 6/40, सू.अ. 5/20, चन्द्रचार वृश्चिक दिन 3/52 से धनु, शु.रा. 8, 10, 11, 2, 3, 6 अ.रा. 9, 12, 1, 4, 5, 7 शुभांक- 0, 3, 7.

व्यापार भविष्य

मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया को ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से रूई, कपास, सूत, के भाव में तेजी होगी, गेहूँ, जौ, चना, गुड़, खांड़ मूँग, मोठ, अरहर के भाव मेंतेजी होगी, भाग्यांक 2623 है.

SUDOKU 7220

	9				6			
4	7				8	3		9
		8	7	3		1	2	
	8	9		5	1		7	6
5	1		8	7		4	9	
	2	4		6	5	7		
7		1	3				5	8
			1				4	

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सू-दोकू 7219

1	9	3	7	5	4	2	6	8
8	4	2	1	6	3	9	7	5
5	7	6	8	2	9	3	1	4
4	1	5	6	3	2	8	9	7
7	2	9	4	8	1	6	5	3
3	6	8	5	9	7	1	4	2
2	5	1	9	4	8	7	3	6
9	8	4	3	7	6	5	2	1
6	3	7	2	1	5	4	8	9